

नो-डिटेंशन पॉलिसी में प्रस्तावति बदलाव का मूल्यांकन

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवीं कक्षा तक के छात्रों को फेल न करने की नीतिको खत्म करने की मंजूरी दे दी है। सरकार इस संबंध में 'बच्चों के लिये निःशुल्क एवं अनविरय शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017' लाने जा रही है।
- शिक्षा के अधिकार के मौजूदा प्रावधान के अनुसार छात्रों को 8वीं कक्षा तक फेल होने के बाद भी अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है, इसे ही हम 'नो-डिटेंशन पॉलिसी' के नाम से जानते हैं।

नो-डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव की ज़रूरत क्यों ?

- नो-डिटेंशन पॉलिसी, शिक्षा के अधिकार अधिनियम (2009) का अहम हिस्सा है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि बच्चों को आठवीं तक किसी भी कक्षा में फेल होने पर उसी कक्षा में पुनः पढ़ने के लिये बाध्य न किया जाए; अगर किसी छात्र के प्राप्तांक कम हैं तो उसे पासगि ग्रेड देकर अगली कक्षा में भेज दिया जाए।
- इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य यह था कि छात्रों की सफलता का मूल्यांकन केवल उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर न किया जाए बल्कि इसमें उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाए।
- कनिष्ठ, इसके लागू होने के कुछ ही वर्षों में यह शिकायत मिलने लगी कि बच्चों में उस कक्षा के स्तर की अपेक्षति जानकारी नहीं है जिस कारण उनके सीखने के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। कहा जा रहा है कि इस पॉलिसी के लागू होने से छात्र और अभिभावक दोनों सुस्त हो गए हैं, जिससे सीखने और सखाने की प्रक्रिया में गिरावट आई है।
- इस पॉलिसी के वरिध में यह भी कहा जा रहा है कि यह "गुड और बैड स्टूडेंट" के बीच में फरक नहीं करती है।

इस बदलाव के नकारात्मक प्रभाव

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को मूल अधिकार बनाने का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को निःशुल्क और अनविरय शिक्षा प्रदान करना है। लेकिन नो-डिटेंशन पॉलिसी में प्रस्तावति बदलाव सामाजिक-आर्थिक कारणों को नज़रअंदाज़ करता दिख रहा है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक, 2014-2015 में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर लगभग 4% थी और बच्चों को परीक्षाओं के आधार पर फेल करने से स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि होगी।
- दरअसल, हमारी समूची शिक्षा व्यवस्था ही लचर है। आर्थिक रूप से वंचित समूहों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे अपने बच्चों को नज्जि ट्यूशन दला सकें। नो-डिटेंशन पॉलिसी में प्रस्तावति इस बदलाव के कारण फेल होने वाले बच्चों को आगे की कक्षाओं में प्रोन्नति नहीं मलि सकेगी और ऐसे में उनके माता-पिता को यह लगना स्वाभाविक है कि बच्चे स्कूल जाने की बजाय कहीं काम पर जाएँ।
- लड़कियों के लिये तो यह बदलाव और भी गंभीर साबित हो सकता है। कम उम्र में विवाह, स्कूलों का घर के नज़दीक न होना, कम लागत वाले सैनटिरी नैपकनि और स्कूलों में शौचालयों का अभाव आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वज़ह से लड़कियाँ माध्यमिक स्तर तक पहुँचते-पहुँचते स्कूल छोड़ देती हैं। अब नो-डिटेंशन पॉलिसी में प्रस्तावति यह बदलाव उनके स्कूल छोड़ने का एक और कारण बन सकता है।
- यह भी देखा गया है कि जब किसी बच्चे को उसकी उम्र से कम उम्र के बच्चों के समूह में बैठने को मज़बूर किया जाता है, तो वह परेशान होता है; दूसरे बच्चे उसका मज़ाक बनाते हैं परणामस्वरूप वह स्कूल छोड़ देता है।

नष्कर्ष

यह ज़रूरी है कि हम वर्तमान शिक्षा पद्धति का नए सरि से मूल्यांकन करें, इसकी पृष्ठभूमि को मनुष्य के समग्र विकास के लिये तैयार करें ताकि आने वाली पीढ़ी केवल सरकारी और कॉर्पोरेट नौकरियों की तरफ न दौड़े बल्कि स्वयं की परख के आधार पर समाज में कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में आदर्श स्थापति करे।

हालाँकि नो-डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव लाने के बाद बच्चों को आगे की कक्षाओं में प्रवेश हेतु अतिरिक्त मौके दिये जाने की बात की जा रही है, लेकिन फरि भी नो-डिटेंशन पॉलिसी को हटाने की इतनी ज़ल्दबाजी ठीक नहीं कही जा सकती है। इस पर गहन अध्ययन की ज़रूरत है और इस प्रक्रिया में इसके विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन होना चाहिये।

